PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 017
दि. 17.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल में सत्ता बदलते ही एक्शन मोड में शुभेंदु सरकार, टीएमसी राज की फाइलें खुलीं तो सियासत में मचा भूचाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब टकराव की राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े फैसलों की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी सरकार पिछले 15 वर्षों के दौरान हुए हर विवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार और कथित फर्जीवाड़े की जांच कराएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठकों और विभिन्न जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने जिस आक्रामक अंदाज में तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है, उसने बंगाल की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। नई सरकार के शुरुआती फैसलों को देखकर यह साफ माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति बेहद संघर्षपूर्ण और आरोप-प्रत्यारोप से भरी रहने वाली है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले उन क्षेत्रों को निशाने पर लिया है जहां भाजपा लंबे समय से चुनावी धांधली और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाती रही है। फाल्टा क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा क्योंकि पिछले लगभग दस वर्षों से वहां के मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने का अवसर नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में वोट देना नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है और यदि किसी क्षेत्र के लोगों को वर्षों तक मतदान से वंचित रखा गया है तो यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां की पूरी स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जाए और स्वतंत्र वातावरण में पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाए।

सत्ता संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने राजनीतिक हिंसा के मामलों पर भी बेहद सख्त रुख अपनाया है। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में उसके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कई लोगों की हत्या हुई और हजारों कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार अतीत को भूली नहीं है और जिन लोगों ने राजनीतिक संरक्षण में हिंसा और अत्याचार किए हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पुराने मामलों में दोबारा एफआईआर दर्ज की जाए और जहां शिकायतें दबा दी गई थीं, वहां तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए।

राज्य सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा जनता के विकास के लिए भेजा गया था, लेकिन पिछली सरकार में उस धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। उन्होंने पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन, फंड वितरण और ठेकों की पूरी जांच की जाए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई पूर्व अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है।

राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की कंपनी 'लिप्स एंड बाउंड्स' का नाम लेकर जांच की बात कही। डायमंड हार्बर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार के पास कंपनी की संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जानकारी पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा और यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दे रही है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल सरकार बदलने की घटना नहीं है, बल्कि राज्य की जनता के लिए "दूसरी आजादी" जैसा क्षण है। उन्होंने दावा किया कि पिछले डेढ़ दशक में राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और प्रशासन को राजनीतिक प्रभाव में काम करने के लिए मजबूर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त कर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेगी।

आसनसोल में हाल ही में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए और दंगों के पीछे किसी राजनीतिक या संगठित साजिश की जांच भी की जाए।

नई सरकार ने सबसे बड़ा संदेश उस फैसले के जरिए दिया है जिसमें दंगाइयों से सरकारी नुकसान की भरपाई उनकी निजी संपत्ति से करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी कीमत आम जनता के टैक्स से नहीं चुकाई जाएगी। नुकसान की पूरी राशि आरोपियों की संपत्ति से वसूली जाएगी। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस भी तेज हो गई है। भाजपा समर्थक इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे डर का माहौल बनाने की कोशिश कह रहे हैं।

इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जारी किए गए एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाणपत्रों की बड़े स्तर पर दोबारा जांच कराने का फैसला लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वर्ष 2011 से 2026 तक जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन किया जाए। यह वही अवधि है जब राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही। नबन्ना सचिवालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार को शिकायतें मिली थीं कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र हासिल किए। अब जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जिन मामलों में दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएं या नियमों का उल्लंघन हुआ हो, वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 15 वर्षों में राज्य में लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिनमें करीब 1 करोड़ एससी, 21 लाख एसटी और लगभग 48 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र शामिल हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। राज्य में पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों की बड़ी आबादी है और जाति प्रमाणपत्र शिक्षा, सरकारी नौकरी तथा विभिन्न योजनाओं में लाभ पाने का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर जांच की प्रक्रिया आने वाले समय में व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दे सकती है।

तृणमूल कांग्रेस ने इन फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार विपक्ष को निशाना बनाने और राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने के बजाय केवल जांच और कार्रवाई की राजनीति कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में कानून का राज स्थापित करने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी है।

बंगाल की राजनीति में यह बदलाव ऐसे समय आया है जब राज्य पहले ही लंबे समय से राजनीतिक ध्रुवीकरण, हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बना हुआ है। अब नई सरकार के फैसलों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक जांच, राजनीतिक टकराव और कानूनी कार्रवाई का दौर और तेज होने वाला है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जिस आक्रामक अंदाज में फैसले ले रहे हैं, उससे यह संकेत मिल रहे हैं कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह नए मोड़ पर पहुंच चुकी है।

पॉक्सो केस में केंद्रीय मंत्री के बेटे पर शिकंजा, देश छोड़ने से रोकने के लिए जारी हुआ लुकआउट नोटिस

हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ की कानूनी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। नाबालिग लड़की से जुड़े पॉक्सो मामले में साइबराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी जांच और गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भागने की कोशिश कर सकता है। इसी आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट, इमिग्रेशन विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि बंदी भगीरथ देश छोड़कर बाहर न जा सकें। साइबराबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है तथा आरोपी की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश जारी है। पुलिस का मानना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदल सकता है, इसलिए जांच एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

इस पूरे मामले में बंदी भगीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार देर रात उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उनके वकील ने अदालत से अपील की कि अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई जाए। हालांकि अदालत ने इस मांग को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद अब पुलिस की कार्रवाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत द्वारा अंतरिम संरक्षण नहीं दिए जाने के बाद जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है।

यह मामला एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ है। पीड़िता की मां ने आठ मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर बंदी भगीरथ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भगीरथ उनकी नाबालिग बेटी के साथ रिश्ते में था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक शिकायत के बाद जब पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया गया तो मामले में और गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं।

जांच अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। पुलिस अब आरोपी और पीड़िता के बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट और अन्य डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है। मामले में फॉरेंसिक टीम की सहायता भी ली जा रही है ताकि सभी तकनीकी पहलुओं की पुष्टि की जा सके।

इस प्रकरण ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज कर दी है क्योंकि आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। विपक्षी दलों ने मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी आरोपी को राजनीतिक पहचान के आधार पर बचाया नहीं जाएगा। पार्टी के कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों को भारतीय कानून में बेहद गंभीर माना जाता है। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए बनाए गए इस कानून में कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस को संवेदनशीलता और तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश होते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपी को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

इस बीच साइबराबाद पुलिस लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि आरोपी जांच प्रक्रिया से बच न सके। लुक-आउट सर्कुलर जारी होने के बाद देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि बंदी भगीरथ कहीं यात्रा करने की कोशिश करें तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए।

तमिलनाडु में नई सरकार का सत्ता संतुलन तय, मुख्यमंत्री विजय ने अपने पास रखे सबसे प्रभावशाली मंत्रालय

चेन्नई। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद अब सत्ता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पूरा खाका सामने आ गया है। राज्य सरकार ने शनिवार को मंत्रियों के विभागों का आधिकारिक बंटवारा कर दिया, जिसके साथ ही नई सरकार की प्राथमिकताएं और शक्ति संतुलन भी साफ दिखाई देने लगा है। अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ दिनों बाद ही अपने पास सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्रालय रखकर यह संकेत दे दिया है कि सरकार की कमान पूरी तरह उनके हाथों में रहेगी। 10 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय ने प्रशासन, कानून व्यवस्था, महिला कल्याण, नगर विकास और युवा मामलों जैसे कई अहम विभाग खुद अपने पास रखे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि एक मजबूत और केंद्रीकृत नेतृत्व का संदेश देने के लिए भी लिया गया है। चूंकि विजय पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी पार्टी ने सीधे सत्ता में प्रवेश किया है, इसलिए वह सरकार के सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली विभागों पर खुद निगरानी रखना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री विजय के पास लोक विभाग, सामान्य प्रशासन, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से जुड़े विभाग, जिला राजस्व प्रशासन, पुलिस और गृह विभाग जैसी अहम जिम्मेदारियां रहेंगी। इसके अलावा विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन, महिला कल्याण, युवा कल्याण, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े विभाग भी उन्होंने अपने पास रखे हैं। नगर प्रशासन, शहरी विकास और जल आपूर्ति विभाग भी सीधे मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे। इन विभागों को सरकार की रीढ़ माना जाता है क्योंकि इनका सीधा संबंध प्रशासनिक नियंत्रण, कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और जनसंपर्क से होता है।

राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि विजय ने अपने पास इतने बड़े मंत्रालय रखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सरकार की कार्यशैली पर व्यक्तिगत रूप से मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। खासतौर पर गृह विभाग और पुलिस प्रशासन अपने पास रखना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से मजबूत नेतृत्व की परंपरा रही है और विजय उसी शैली को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं।

सरकार में शामिल अन्य मंत्रियों को भी उनके अनुभव और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर विभाग सौंपे गए हैं। एन. आनंद को ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है। यह विभाग गांवों के विकास, पंचायत व्यवस्था और सिंचाई परियोजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट और कृषि से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे हैं, इसलिए इस मंत्रालय की जिम्मेदारी काफी अहम मानी जा रही है।

आधव अर्जुना को लोक निर्माण और खेल विकास विभाग सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग राज्य की सड़क, भवन और आधारभूत संरचना परियोजनाओं का प्रमुख विभाग होता है। वहीं खेल विकास विभाग को युवाओं के बीच सरकार की छवि मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार आने वाले समय में खेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे सकती है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी डॉ. के.जी. अरुणराज को दी गई है। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य विभाग को सबसे संवेदनशील मंत्रालयों में गिना जाता है। अस्पतालों की स्थिति, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे मुद्दे इस मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती होंगे।

वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। किसी भी सरकार में वित्त विभाग को सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों में गिना जाता है क्योंकि राज्य की आर्थिक नीतियां, बजट और विकास योजनाओं के लिए धन आवंटन इसी विभाग के जरिए तय होता है। तमिलनाडु पहले से ही आर्थिक चुनौतियों और बढ़ते कर्ज के मुद्दों से जूझ रहा है, ऐसे में नए वित्त मंत्री की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है।

पी. वेंकटरामनन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का जिम्मा इसी मंत्रालय के पास रहेगा। तमिलनाडु में गरीब और मध्यम वर्ग के बीच यह विभाग राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध आम जनता से होता है।

आर. निर्मलकुमार को ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्रालय सौंपा गया है। ऊर्जा विभाग राज्य की बिजली आपूर्ति और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, जबकि कानून विभाग प्रशासनिक और संवैधानिक मामलों में सरकार को दिशा देता है। राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता बेहद जरूरी मानी जाती है।

पानीपुरी में हड्डी का टुकड़ा मिलने से मचा बवाल, वायरल वीडियो ने स्ट्रीट फूड की स्वच्छता पर खड़े किए बड़े सवाल

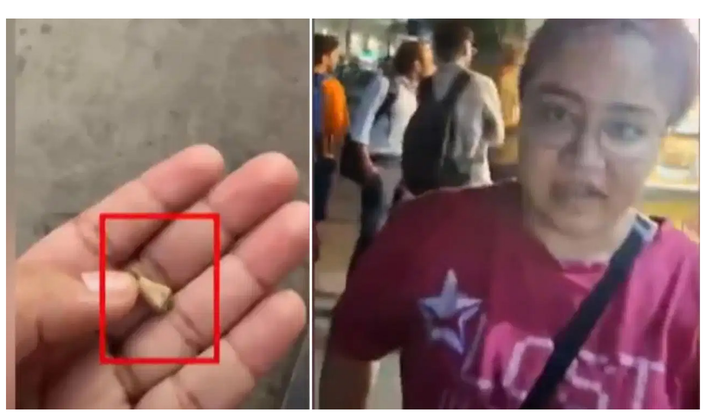

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आई एक घटना ने स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर के रानीप इलाके में एक पानीपुरी स्टॉल पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती को गोलगप्पे के पानी में कथित तौर पर हड्डी का टुकड़ा मिला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वायरल वीडियो ने न केवल स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की साफ-सफाई पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर भी नई बहस शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद के रानीप बस स्टॉप के पास स्थित 'कृष्णा पानीपुरी' नामक स्टॉल पर एक युवती रात के समय पानीपुरी खाने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही उसने एक गोलगप्पा खाया, उसे मुंह में कुछ अजीब महसूस हुआ। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई कठोर मसाला या अन्य चीज होगी, लेकिन जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह कथित तौर पर हड्डी का टुकड़ा जैसा दिखाई दिया। यह देखकर युवती हैरान रह गई और मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी हलचल मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवती ने तुरंत स्टॉल संचालक से इस बारे में शिकायत की और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। कुछ देर तक वहां बहस का माहौल बना रहा। आसपास मौजूद लोग भी इस घटना को देखकर चौंक गए। युवती ने स्टॉल मालिक से जवाब मांगा कि आखिर खाने की सामग्री में ऐसी चीज कैसे पहुंची। मामले को बढ़ता देख स्टॉल संचालक ने माफी मांग ली, लेकिन तब तक यह मामला लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका था।

घटना के बाद युवती ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने कथित हड्डी का टुकड़ा भी दिखाया। उसने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कई लोगों ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल माफी काफी नहीं है और खाद्य सुरक्षा विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वायरल वीडियो के बाद लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर बिना किसी निगरानी के खुलेआम बिक रहे स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता की जांच कौन करता है। कई यूजर्स ने लिखा कि सड़क किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों में साफ-सफाई की अनदेखी आम बात हो गई है और प्रशासन अक्सर कार्रवाई केवल शिकायत आने के बाद ही करता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि धार्मिक भावनाओं और लोगों के स्वास्थ्य दोनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्ट्रीट फूड भारत की खाद्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। पानीपुरी, भेलपुरी, चाट, कचौरी और अन्य स्नैक्स देशभर में बेहद लोकप्रिय हैं। बड़ी संख्या में लोग रोजाना इनका स्वाद लेने के लिए सड़क किनारे दुकानों और ठेलों पर पहुंचते हैं। लेकिन इसी के साथ स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। कई बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां खाने में कीड़े, गंदगी या अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलने की शिकायतें हुई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। यदि खाने की सामग्री को ढककर नहीं रखा जाए या स्वच्छ पानी का उपयोग न हो तो संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में खाद्य विभाग की नियमित जांच और सख्त निगरानी बेहद आवश्यक मानी जाती है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि शहर में स्ट्रीट फूड स्टॉलों की जांच अभियान चलाया जाए। लोगों का कहना है कि केवल लाइसेंस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय-समय पर गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच भी होनी चाहिए। कई लोगों ने यह भी मांग की कि जिन स्टॉलों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे कथित हड्डी के टुकड़े को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे बेहद गंभीर लापरवाही बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घटना ने शहर में चर्चा का माहौल जरूर पैदा कर दिया है।

युवती ने वीडियो में यह भी कहा कि वह केवल अपने साथ हुई घटना को लोगों के सामने लाना चाहती थी ताकि दूसरे लोग सतर्क रहें। उसने प्रशासन से स्टॉल संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने युवती की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को सामने लाना जरूरी है ताकि खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ सके। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि स्वाद के साथ-साथ स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थ लोगों के बीच चाहे जितने लोकप्रिय हों, लेकिन यदि उनमें साफ-सफाई और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाए तो वे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

संपादकीय

चौतरफा महंगाई

बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आंकड़ों से पता चला कि एक माह के भीतर ही थोक महंगाई दर दुगनी हो गई है। जो कि पिछले 42 महीनों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। अब शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल तथा सीएनजी के दामों में वृद्धि ने आम आदमी को व्यथित कर दिया। जाहिर है पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि से न केवल यातायात महंगा हो जाता है बल्कि मालभाड़ा बढ़ने से हर चीज के दामों में उछाल आ जाता है। वहीं रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियां दुहाई दे रही हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि से उनकी उत्पादन लागत में दस से बीस फीसदी की वृद्धि हुई है। फलतः इन कंपनियों ने छूट व प्रचार खर्च में कटौती करके भंडारण क्षमता व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना प्राथमिक लक्ष्य बनाया है। अतः देश की एफएमसीजी रोजमर्रा के सामान की लागत बढ़ने व मुनाफे पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिये चरणबद्ध तरीके से वस्तुओं के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। यह भी हकीकत है कि पिछली तिमाही में ये एफएमसीजी पहले ही तीन से पांच प्रतिशत की वृद्धि वस्तुओं की कीमतों में कर चुकी हैं। फलतः आम उपभोक्ता को अभी और महंगाई को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी एक हकीकत है कि रुपये के गिरते मूल्य ने भी कीमतें बढ़ाने का दबाव बनाया है। कंपनियां अपना मुनाफा बनाये रखने के लिये कीमतें बढ़ाने और पैकेटबंद उत्पादों की मात्रा घटाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। आशंका जतायी जा रही है कि पेट्रोल व डीजल के दामों में तीन-तीन रुपये की वृद्धि के बाद टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान बढ़ा सकती हैं। उनका दावा है कि मोबाइल टॉवर को चलाने में आने वाला 40 फीसदी खर्च सिर्फ पेट्रोल और बिजली पर होता है। यह खर्चा टैरिफ बढ़ाकर ग्राहकों पर डाला जा सकता है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां कह रही हैं कि होर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद उन्होंने मामूली वृद्धि पेट्रोल व डीजल के दामों में की है।

निश्चित रूप से पश्चिम एशिया संकट के चलते उपजे हालात ने बताया है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा नीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के आह्वान के कुछ दिन बाद ही पेट्रोल, डीजल व सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी चार साल से अधिक समय में पहली बार की गई है। निस्संदेह, खाड़ी संकट से उपजे हालात में कीमतों में यह वृद्धि अनिवार्य लग रही थी। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के चलते ही सरकार ने यह कदम देर से उठाया है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ईंधन खपत में कटौती करने का आगाह किया था, तो संकेत माना गया कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान की ओर इशारा करते हुए मूल्य वृद्धि का बचाव किया है। रिपोर्ट बताती है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के रिटेलर्स रोजाना एक हजार करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं,जबकि कच्चे तेल की कीमत सौ डॉलर प्रति बैरल थी। निस्संदेह, पहले ही मुद्रास्फीति व स्थिर आय से जूझ रहे नागरिकों को सरकार की यह दलील गले नहीं उतरेगी। वैसे भी चुनावी रणनीति के मद्देनजर संचालित आर्थिक निर्णय सार्वजनिक विश्वास में कमी लाते हैं। जाहिर बात है कि करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार, किसान व छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोगों के लिए बढ़ी ईंधन दरें जल्दी ही भोजन, परिवहन और आवश्यक वस्तुओं को महंगा बना देती हैं। फिक्र की बात यह है कि भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता अर्थव्यवस्था को भू राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील बना देती है। रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल हमें अस्थायी राहत ही प्रदान करता है। लेकिन यह मार्ग भी प्रतिबंधों, शिपिंग रुकावटों और कूटनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। यह संकट भारत को दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति बनाने के लिये बाध्य करता है। हमारी प्राथमिकता सार्वजनिक परिवहन विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग व नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की होनी चाहिए।

कब तक होगा परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़?

> करोड़ों लोग नीट परीक्षा लीक कांड की जांच को अब धूमिल होते देख रहे हैं। तसल्ली उन अभिभावकों को भी कर लेनी चाहिए,जो न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। निष्पिक्ष जांच-पड़ताल की आस अब इसलिए भी नहीं की जा सकती। क्योंकि पूरा सिस्टम जांच छोड़कर, बड़ी मछलियों को बचाने में ही जुटेगा।

'नीट प्रश्नपत्र लीक' मामले में गिरफ्तारियों की धरपकड़ जारी है। पड़ताल का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। राजस्थान से कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए हैं वह सियासत से संबंध रखते हैं। पुलिस अभिरक्षा में उनका सार्वजनिक रूप से मीडिया के कैमरों पर बोलना कि वह तो मौहरे मात्र हैं। खिलाड़ी तो कोई और ही हैं वह बडे-बड़े स्तर के? आरोपियों के मुख से निकले ये शब्द निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच की उम्मीदों पर ग्रहण लगाने के लिए प्याप्त हैं। यहीं से मुकम्मल जांच की उम्मीदें टूटती दिखाई पड़ती हैं। साढ़े 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ हुआ इतना बड़ा खिलवाड़ भी क्या एक कहानी बनकर सरकारी फाइलों में सिमट जाएगा? करोड़ों लोग नीट परीक्षा लीक कांड की जांच को अब धूमिल होते देख रहे हैं। तसल्ली उन अभिभावकों को भी कर लेनी चाहिए,जो न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। निष्पिक्ष जांच-पड़ताल की आस अब इसलिए भी नहीं की जा सकती। क्योंकि पूरा सिस्टम जांच छोड़कर, बड़ी मछलियों को बचाने में ही जुटेगा। ऐसा इस बार नहीं, पिछले तकरीबन सभी पेपर लीक कांडों में हुआ। नीट दाखिला परीक्षा है, भर्ती की पूरी की पूरी परीक्षा भारत में लीक होने लगी हैं। बावजूद इसके केंद्रीय हुकूमत कोई ऐसा उपाय नहीं कर पा रही जिससे परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ रूक सके।

पिछले 7 वर्षों में यानी 2019 से लेकर 2026 मई तक, भारत में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगी लगभग 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आज तक किसी मामले की जांच न पूरी हुई और ना किसी मामले में

न्याय हुआ। प्रत्येक मामलों में छोटे स्तर के कर्मचारी ही पकडे.गए जिन्हें कुछ महीनों बाद या एकाध वर्षों में जमानत मिल गई। सबसे पहले दाखिला परीक्षा कराने वाली एनटीए को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए। एनटीए का कार्य इसलिए भी अब संतोषजनक नहीं, क्योंकि वह पुराने तौर-तरीकों को अभी भी अपनाती है।अपने सिस्टम को रिफॉर्म भी नहीं करती। विश्व की प्रतिष्ठित भरोसेमंद परीक्षाओं से भी कुछ नहीं सीखती। इंटरनेट-कंप्यूटर के जमाने में भी प्रश्न पत्र मुद्रित करके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने में विश्वास करती है।अगर ऐसा ही करना है तो प्रश्पपत्रों के सेट बदले हुए और अलग-अलग होने चाहिए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावनाएं न हो। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी, तो पूरी परीक्षा रद ना की जाए, सिर्फ उसी सेंटर पर दोबारा परीक्षा करवाई जाए, जहां कुछ गड़बड़ी हुई हो? अगर ऐसे आधुनिक तरीके अपनाए जाते तो परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ न होता।

केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी अच्छे से जानती हैं कि भारत में आयोजित होने वाली हर चौथी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर का लीक होता है जिसमें पुलिस भर्ती और शिक्षा परीक्षाएं कुख्यात हैं। जबकि, नीट परीक्षा नौकरी या भर्ती की परीक्षा नहीं होती, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होती है उसमें भी सेंधमारी, हद है? गौरतलब है अगर पूर्ववर्ती पेपर लीक मामलों में सख्ती और स्वतंत्र-निष्पक्ष जांच हुई होती और आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए गए होते और सजा के तौर पर उम्रकैद या मोटा हर्जाना वसूला गया होता, तो ऐसे कांड करने वाले भय खाते, डरते। भविष्य में गड़बड़ी करने से तौबा भी करते? लेकिन लचीला कानून-प्रशासन का उदार रवैया और कमजोर सजा-जुर्माने से आरोपी तनिक भी नहीं डरते। एक कांड करते हैं दूसरे की तैयारी में लगे होते हैं। फिलहाल मौजूदा नीट पेपर कांड पहला दोष तो परीक्षा कराने वाली संस्था 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' यानी एनटीए का ही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की पात्रता परीक्षा नीट के सवाल लीक होने से पूरी परीक्षा रद्द करने की मजबूरी जितनी शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक।

एनटीए का गठन 2017 में हुआ, तब से लेकर आज तक इस संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही। 5 मई 2024 को भी जब इसी नीट परीक्षा में गडबड़झाला हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब संस्था ने भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करने का आश्वासन न सिर्फ अदालत को दिया था बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी भरोषा दिया था? पर, बेशर्मी देखिए मात्र 24 महीनों बाद भी उससे पहले से भी बड़ा कांड़ कर दिया। पिछली दफा इन्होंने कई छात्रों को पूरे-पूरे 720 नंबर दे डाले थे,जबकि वो सभी छात्र पढ़ने में सामान्य थे उनके मुकाबले टॉपरों को उनसे कहीं कम नंबर दिए गए थे। इस बार तो उससे भी बड़ा ब्लंडर हुआ। पेपर लीक की सूचना सबसे पहले राजस्थान से बाहर निकली। जहां, कई छात्रों के पास 140 से अधिक परीक्षा के मूल प्रश्नों से हूबहू प्रश्न गेस पेपरों में मिले।

लीक प्रश्नों पर सबसे पहले एनटीए की ओर से सफाई दी गई कि प्रश्न प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए। जबकि, सभी जानते हैं कि जहां पेपरों की छपाई होती है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बेहद गुप्त स्थान होता है और वहां के कर्मचारियों को फोन तक रखने की इजाजत नहीं होती। ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्नों के लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। इस कांड में पूरा का पूरा सिंडिकेट शामिल होता है। समय का तकाजा है ऐसी विधि केंद्रीय लेबल पर बननी चाहिए, ताकि छात्रों के जीवन से कोई खिलवाड़ न कर पाए। केंद्र सरकार को आगे आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि मौजूदा कांड में हुकूमत की चुप्पी सभी को अखर रही है। ऐसी घटनाओं के घट जाने के बाद छात्र सिर्फ सरकार से ही न्याय की उम्मीद करते हैं।

प्रेरणा

मृत्यु की छाया में जागता सत्य

मनुष्य का जीवन जितना आकर्षक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही भय और असुरक्षा से भरा होता है। धन, वैभव, सत्ता और सुख-सुविधाएं बाहर से चमकती अवश्य हैं, परंतु मृत्यु का एक विचार इन सबकी चमक को पलभर में फीका कर देता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, फिर भी मनुष्य उससे आंखें चुराकर जीना चाहता है। वह स्वयं को अमर मानकर भोग-विलास में डूबा रहता है। इतिहास और अध्यात्म में अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो यह समझाती हैं कि वास्तविक शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से ऊपर उठने में है। सम्राट अशोक और उनके छोटे भाई वीतशोक की कथा इसी सत्य को अत्यंत मार्मिक ढंग से उजागर करती है।

सम्राट अशोक अपने समय के महान और बुद्धिमान शासक माने जाते थे। कलिंग युद्ध के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। रक्तपात और विनाश देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर अहिंसा, दया और धर्म के मार्ग को स्वीकार किया। वे श्रमण-भिक्षुओं का अत्यंत सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि संसार के मोह और मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग अध्यात्म ही है। लेकिन उनके छोटे भाई वीतशोक इस सत्य को नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि भिक्षु केवल उत्तम भोजन और वस्त्रों के लोभ में संन्यास धारण करते हैं। उनके लिए त्याग और वैराग्य केवल दिखावा था।

अशोक जानते थे कि केवल शब्दों से किसी को सत्य का अनुभव नहीं कराया जा सकता। जब तक मनुष्य स्वयं भीतर से न जागे, तब तक उपदेश व्यर्थ होते हैं। इसलिए उन्होंने एक युक्ति बनाई। एक दिन मंत्रियों ने वीतशोक को समझाया कि सम्राट के बाद वही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, इसलिए उन्हें राजसी वस्त्र और आभूषण धारण कर सिंहासन पर बैठना चाहिए। वीतशोक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजसी पोशाक पहनी, बहुमूल्य आभूषण धारण किए और गर्व से सिंहासन पर बैठ गए। उन्हें लगा मानो संसार का सबसे बड़ा सुख उन्हें प्राप्त हो गया हो। उसी समय सम्राट अशोक वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोध का अभिनय करते हुए कहा कि उनके रहते सिंहासन पर बैठने का साहस करना राजद्रोह है और इसके लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनते ही वीतशोक के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी जो व्यक्ति कुछ क्षण पहले गर्व और आनंद से भरा था, वह भय से कांपने लगा। मंत्रियों ने बहुत विनती की, तब अशोक ने कहा कि चूंकि वह उनके प्रिय भाई हैं, इसलिए उन्हें एक सप्ताह तक राजसुख भोगने का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद दंड दिया जाएगा।

अब वीतशोक सात दिनों के लिए राजा बने। उनके सामने स्वादिष्ट भोजन थे, चारों ओर सेवक खड़े थे, सुंदर वस्त्र और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हर समय उनके पीछे दो खड्गधारी सैनिक चलते रहते, जिनकी नंगी तलवारें उन्हें यह याद दिलाती रहतीं कि सात दिन बाद मृत्यु निश्चित है। यही विचार उनके मन पर इतना भारी पड़ गया कि उन्हें किसी सुख में आनंद ही नहीं आया। न स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगा, न राजमहल की भव्यता। रातों की नींद गायब हो गई। हर क्षण मृत्यु का भय उनके मन को जकड़े रहा।

सात दिन बाद उन्हें सम्राट के सामने लाया गया। अशोक ने मुस्कराकर पूछा कि राजपद का सुख कैसा लगा। वीतशोक का उत्तर अत्यंत मार्मिक था। उन्होंने कहा कि जहां हर समय मृत्यु सामने खड़ी हो, वहां सुख और भोग-विलास का क्या अर्थ रह जाता है? जिस व्यक्ति को यह ज्ञात हो कि उसका अंत निकट है, उसके लिए संसार का कोई आकर्षण महत्व नहीं रखता।

तभी अशोक ने उन्हें जीवन का गहरा सत्य समझाया। उन्होंने कहा कि तुम केवल एक निश्चित मृत्यु के भय से सुख नहीं भोग सके, जबकि श्रमण-भिक्षु तो जन्म-जन्मांतर के मृत्यु-भय से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। वे भोजन और वस्त्र के लिए संन्यासी नहीं बने, बल्कि उन्होंने उन तुच्छ इच्छाओं को पार कर लिया है। उनका लक्ष्य उस भय को समाप्त करना है जो मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक बांधे रखता है।

यह कथा केवल प्राचीन इतिहास की घटना नहीं, बल्कि आज के मनुष्य के जीवन का दर्पण है। आज भी लोग धन, पद, प्रसिद्धि और सुख-सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। वे सोचते हैं कि अधिक पैसा और बड़ा पद उन्हें सुरक्षित और सुखी बना देगा। लेकिन भीतर कहीं मृत्यु का भय हर व्यक्ति के साथ चलता रहता है। कोई बीमारी का डर लेकर जीता है, कोई असफलता से डरता है, कोई अपनों को खोने से भयभीत रहता है। बाहर से मुस्कराता हुआ व्यक्ति भी भीतर से असुरक्षित हो सकता है।

आधुनिक जीवन में मनुष्य ने सुविधाएं तो बहुत बढ़ा ली हैं, लेकिन मानसिक शांति खो दी है। कारण यह है कि उसने बाहरी उपलब्धियों को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वह भूल गया कि जीवन क्षणभंगुर है। मृत्यु का स्मरण यदि सही रूप में किया जाए तो वह निराशा नहीं, बल्कि जागरण का कारण बनता है। यह स्मरण मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे यह समझाता है कि समय सीमित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। भारतीय दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि परिवर्तन माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह केवल भोग और संग्रह में जीवन नष्ट नहीं करता, बल्कि सत्य, करुणा और आत्मिक विकास की ओर बढ़ता है।

सम्राट अशोक की यह युक्ति इसलिए महान थी क्योंकि उन्होंने अपने भाई को भय का अनुभव कराकर सत्य का बोध कराया। कभी-कभी जीवन के बड़े सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आते हैं। मृत्यु का भय मनुष्य को तोड़ भी सकता है और जगा भी सकता है। जो व्यक्ति इस भय में डूब जाता है, वह जीवनभर अशांत रहता है। लेकिन जो इसे समझकर आत्मबोध की ओर बढ़ता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है।

वास्तविक सुख बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि उस मानसिक अवस्था में है जहां मृत्यु का भय मनुष्य को विचलित न कर सके। जिसने जीवन के अनित्य स्वरूप को समझ लिया, वही वास्तव में मुक्त है। वही संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ सकता है। यही इस कथा का संदेश है कि मृत्यु से भागकर नहीं, बल्कि उसे समझकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।

Old Gold Exchange Schemes पर टूट रहे ग्राहक, 18 Carats Bridal Jewellery Collections बाजार में छाए

भारत में सोना और चांदी की बढ़ती मांग, वैश्विक अस्थिरता और आयात पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार, आभूषण उद्योग और खुदरा कंपनियां अब घरों और मंदिरों में पड़े निष्क्रिय सोने को फिर से अर्थव्यवस्था में लाने की दिशा में सक्रिय हो गई हैं। सरकार ने 12 मई को सोना और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इसका उद्देश्य लगातार बढ़ रहे आयात को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को कम करना है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वह एक वर्ष तक सोने की खरीद टालने पर विचार करें ताकि देश की आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक बोझ कम हो सके। हम आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है और अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का सोना आयात बढ़कर लगभग 68.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2016-17 में यह केवल 9.7 अरब डॉलर था। वहीं चांदी का आयात भी एक दशक में तेजी से बढ़ा है और 2025-26 में यह 11.4 अरब डॉलर से अधिक हो गया। दूसरी ओर निर्यात बेहद कम है, जिससे व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और पेरू भारत के प्रमुख सोना आपूर्तिकर्ता हैं, जबकि चांदी मुख्य रूप से ब्रिटेन, हांगकांग और अमेरिका से आयात की जाती है।

आभूषण उद्योग का मानना है कि यदि भारतीय घरों और मंदिरों में जमा निष्क्रिय सोने का एक हिस्सा भी औपचारिक व्यवस्था के माध्यम से बाजार में वापस लाया जाए, तो आयात पर निर्भरता काफी कम हो सकती है। टाइटन कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी अशोक सोनथालिया ने कहा कि भारत के नागरिकों और मंदिरों के पास दुनिया का सबसे बड़ा जमीन के ऊपर मौजूद स्वर्ण भंडार है। टाइटन ने लगभग 25 वर्ष पहले पुराना सोना विनिमय कार्यक्रम शुरू किया था और वर्तमान में उसकी कुल सोना जरूरत का लगभग 50 प्रतिशत इसी माध्यम से पूरा होता है। कल्याण ज्वैलर्स ने भी "नेशन फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया" पहल की घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में पांच टन सोना आयात कम करना है। इसके तहत पुराने सोने के विनिमय कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा, हल्के वजन के 18 कैरेट आभूषणों को प्रोत्साहित किया जाएगा और स्वर्ण मुद्रीकरण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। कंपनी अपने 342 स्टोरों में विशेष काउंटर स्थापित करेगी, जहां ग्राहक पारदर्शी व्यवस्था के तहत सोने को नकद में बदल सकेंगे। कंपनी के अनुसार उसके कारोबार में पुराने सोने के विनिमय की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।

उधर, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कई सुझाव दिए हैं। परिषद का कहना है कि कम कैरेट वाले आभूषणों की बिक्री बढ़ाने से सोना आयात में 20 से 30 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। साथ ही पुराने सोने को नए आभूषणों में बदलने की संस्कृति को बढ़ावा देना भी जरूरी है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने भी सरकार को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को और प्रभावी बनाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के अध्यक्ष एमपी अहमद के अनुसार भारतीय परिवारों के पास भारी मात्रा में निष्क्रिय सोना मौजूद है और यदि उसका कुछ हिस्सा भी औपचारिक व्यवस्था में वापस आए तो नए आयात की आवश्यकता काफी कम हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय परिवार आमतौर पर आभूषण और सोने के सिक्के खरीदकर बैंक लॉकरों में सुरक्षित रखते हैं। यह सोना लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है जबकि इसका पुनर्चक्रण देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी हो सकता है। उद्योग जगत अब 22 कैरेट की बजाय 18 और 14 कैरेट के हल्के आभूषणों को बढावा देने पर भी जोर दे रहा है। टाइटन ने हाल ही में 18 कैरेट में दुल्हन आभूषणों का नया संग्रह पेश किया है। इधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण तेल कीमतों में तेजी आई है। इसके चलते मुद्रास्फीति बढ़ने और ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से सोने की कीमतों पर दबाव बना है। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में 13 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर मजबूत होने और अमेरिकी बांड प्रतिफल बढ़ने से निवेशकों का रुझान भी सोने से दूर हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ती तेल कीमतों ने मुद्रास्फीति की आशंकाओं को फिर बढ़ा दिया है, जिससे बाजार में ब्याज दरों को लेकर संशय पैदा हो गया है। इस बीच, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। इससे भारत जैसे आयात आधारित देशों पर दोहरा दबाव बन रहा है क्योंकि देश अपनी 85 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतें भी विदेशों से पूरी करता है। ऐसे में सोना और तेल दोनों के बढ़ते आयात से चालू खाता घाटा और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि सरकार अब नागरिकों से गैर जरूरी सोना और चांदी खरीद में संयम बरतने की अपील कर रही है।

अभियान

वट वृक्ष की छांव में बसता है अखंड सौभाग्य का रहस्य

भारतीय संस्कृति में प्रकृति और धर्म का संबंध अत्यंत गहरा माना गया है। यहां नदियों को मां कहा जाता है, पर्वतों को देवस्वरूप माना जाता है और वृक्षों को जीवनदाता के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं पवित्र वृक्षों में बरगद यानी वट वृक्ष का विशेष स्थान है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत के दिन इस वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आने वाला यह पर्व भारतीय परंपरा, नारी शक्ति और अटूट वैवाहिक विश्वास का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखकर विधि-विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनती हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 12 मिनट से 08 बजकर 24 मिनट तक माना गया है, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करती हैं, नए या साफ-सुथरे वस्त्र धारण करती हैं और सुहाग की सभी वस्तुएं पहनती हैं। इसके बाद वे वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करती हैं। पूजा के दौरान वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाए जाते हैं तथा कच्चे सूत को पेड़ के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। महिलाएं पूरे श्रद्धाभाव से अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करती हैं।

वट सावित्री व्रत का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी कथा और उससे जुड़ा आध्यात्मिक संदेश है। यह व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय नारी की निष्ठा, साहस और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा सदियों से भारतीय समाज में आदर्श दांपत्य जीवन का उदाहरण मानी जाती है। कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन ऋषियों ने चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह जानने के बाद भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उसने सत्यवान से विवाह किया और पूरे समर्पण के साथ वैवाहिक जीवन निभाने लगी।

समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़े। वहीं उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहां पहुंचे और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे कई बार समझाया कि वह लौट जाए, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण पीछे हटने को तैयार नहीं हुई।

सावित्री की निष्ठा और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर उसने अपने पिता के लिए सौ पुत्रों का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी सौ पुत्रों का वरदान मांग लिया। तब यमराज समझ गए कि बिना पति के यह संभव नहीं हो सकता। सावित्री की चतुराई, धैर्य और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाने लगा।

बरगद के पेड़ को इस व्रत में विशेष महत्व मिलने के पीछे भी गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। यह वृक्ष वर्षों तक जीवित रहता है और इसकी शाखाएं लगातार फैलती रहती हैं। इसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली होती हैं, जो इसे मजबूती और स्थायित्व प्रदान करती हैं। यही कारण है कि इसे मजबूत रिश्तों, दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इस प्रकार यह वृक्ष सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक बन जाता है।

भारतीय संस्कृति में पेड़ों की पूजा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बरगद का वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह दिन-रात ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ों में गिना जाता है। इसकी घनी छाया गर्मी से राहत देती है और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में सहायता करती है। गांवों में बरगद का पेड़ सामाजिक जीवन का केंद्र हुआ करता था। इसके नीचे पंचायतें लगती थीं, धार्मिक आयोजन होते थे और लोग विश्राम करते थे। इस प्रकार यह वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। वट सावित्री व्रत का संदेश आज के आधुनिक समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आज के समय में जहां रिश्तों में धैर्य और विश्वास की कमी देखने को मिलती है, वहां यह व्रत पति-पत्नी के बीच समर्पण, विश्वास और प्रेम का महत्व समझाता है। यह व्रत केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पारिवारिक मूल्यों और संबंधों की मजबूती का प्रतीक भी है। सावित्री की कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सुख के समय साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहने का नाम है।

भारतीय समाज में नारी को हमेशा शक्ति और त्याग का प्रतीक माना गया है। वट सावित्री व्रत इसी शक्ति और समर्पण का उत्सव है। सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ निश्चय, बुद्धिमानी और विश्वास के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज तक को अपने प्रेम और तर्क से प्रभावित कर दिया। यही कारण है कि भारतीय महिलाएं सावित्री को आदर्श पतिव्रता के रूप में पूजती हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेती हैं।

इस व्रत का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। जिस संस्कृति में पेड़ों को देवतुल्य माना जाता है, वहां पर्यावरण की रक्षा अपने आप एक धार्मिक कर्तव्य बन जाती है। आज जब दुनिया पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब भारतीय परंपराओं का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वट वृक्ष की पूजा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को भी दर्शाती है। आज भी भारत के गांवों और शहरों में महिलाएं पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यह व्रत करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं समूह में एकत्र होकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनती हैं। पूजा के दौरान वातावरण भक्ति और आस्था से भर जाता है। महिलाएं अपने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। यह पर्व सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वट सावित्री व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के गहरे मूल्यों को समझाने वाला पर्व है। यह व्रत प्रेम, विश्वास, समर्पण, धैर्य और पारिवारिक एकता का संदेश देता है। बरगद का विशाल और अडिग वृक्ष यह सिखाता है कि रिश्तों की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, जीवन उतना ही स्थिर और सुखी होगा। उसकी फैली हुई शाखाएं समृद्धि और संरक्षण का प्रतीक हैं, जबकि उसकी लंबी आयु यह संदेश देती है कि सच्चे संबंध समय की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि यहां हर पर्व और परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा होता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

साबरकाँठा जिले में निर्मित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क पर्यटकों में जगा रहा है आकर्षण, 2 महीनों में 3000 से अधिक लोग आए

▶▶ 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित यह पार्क गुजरात से गुजरने वाली कर्क रेखा के भौगोलिक एवं खगोलीय महत्व के बारे में जानकारी देता है

▶▶ एक सेल्फ-एक्सप्लेनेटरी पार्क; जहाँ एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स तथा आगंतुकों के लिए सुविधा उपलब्ध, गर्मी की छुट्टियों को बनाएगा दिलचस्प

गांधीनगर : गुजरात के नागरिक और विशेषकर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा गुजरात से गुजरने वाली कर्क रेखा के भौगोलिक महत्व के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत कार्यरत 'गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (गुजकोस्ट) द्वारा साबरकाँठा जिले में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गत 11 मार्च, 2026 को साबरकाँठा जिले के सलाल गाँव में इस पार्क का उद्घाटन किया गया था, जो राज्य में विज्ञान विषय की शिक्षा तथा जागरूकता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिक रुझानों /झुकावों को प्रोत्साहन देने और बच्चों में आधुनिक विज्ञान की क्षमताओं के बारे में समझ विकसित करने पर सदैव बल दिया है।

यह साइंस पार्क आगंतुकों के लिए विज्ञान पर्यटन के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। पर्यटकों में और विशेष रूप से विज्ञान में रुचि रखने वाले आगंतुकों में यह पार्क अब अनूठा आकर्षण उत्पन्न कर रहा है। उद्घाटन होने के बाद 2 महीने की समयावधि में लगभग 3500 से अधिक आगंतुक टॉपिक ऑफ साइंस पार्क देखने के लिए आ चुके हैं और इस समय जब गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तब आगंतुकों की संख्या में वृद्धि होगी।

8 करोड़ रुपए की लागत से 5,930 वर्ग मीटर में विकसित साइंस पार्क

उल्लेखनीय है कि गुजकोस्ट द्वारा 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित किए गए इस पार्क के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि नागरिकों तथा विशेषकर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक रुझान / झुकाव विकसित करने के लिए ऐसी पहलें महत्वपूर्ण हैं।

यह पार्क कर्कवृत्त तथा कर्क रेखा के भौगोलिक एवं खगोलीय महत्व को समझाने के लिए एक इंटरेक्टिव शैक्षिणक तथा अनुसंधान केन्द्र के रूप में सेवा देगा, जिसमें पृथ्वी व सूर्य के बीच के संबंध तथा ऋतुगत परिवर्तन शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश पृथ्वी के ऐसे भाग हैं, जो पृथ्वी के केन्द्र के निकट हैं और अति समृद्ध जैवविविधताओं से युक्त हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश लगभग 40 प्रतिशत भूमि क्षेत्र को समाविष्ट करते हैं, जो कर्कवृत्त तथा मकरवृत्त के बीच आता है।

ट्रॉपिक ऑफ सेंटर (टीओसी) यानी कर्कवृत्त हमारी पृथ्वी को विभाजित करने वाले पाँच मुख्य अक्षांश वृत्तों में एक है, जिसे उत्तरीय उष्णकटिबंध के रूप में भी जाना जाता है। वह पृथ्वी पर स्थित सबसे उत्तरीय अक्षांश वृत्त है, जहाँ सूर्य उसकी पराकाष्ठा पर सीधे सिर के ऊपर देखा जा सकता है।

कर्क रेखा गुजरात के सात जिलों से गुजरती है

कर्कवृत्त विषुववृत्त से 23.50 डिरी उत्तर के कोण पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है; जो भारत सहित 16 देशों, 3 महाद्वीपों तथा विश्वभर के 6 जल संग्रहों से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा आठ राज्यों से गुजरती है; जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम शामिल हैं।

गुजरात में जिन सात जिलों से कर्क रेखा गुजरती है; उनमें (1) अरवल्ली, (2) साबरकाँठा, (3) गांधीनगर, (4) मेहसाणा, (5) सुरेन्द्रनगर, (6) पाटण तथा (7) कच्छ शामिल हैं। कर्क रेखा गुजरात की उत्तरीय सीमा से गुजरती है, जिसके कारण राज्य में बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा वातावरण रहता है।

कर्कवृत्त (टीओसी) तथा उसके महत्व के बारे में जागरूकता तथा समझ विकसित करने और इस साइट को एक शोध केन्द्र (एक्सप्लोरेशन पॉइंट) के रूप में विकसित करने के लिए साबरकाँठा जिले में हिम्मतनगर राजमार्ग पर यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क विकसित किया गया है।

खुले आकाश तले विज्ञान की जीवंत प्रयोगशाला

ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विज्ञान को केवल पढ़ा ही नहीं जाता, बल्कि अनुभव भी किया जा सकता है। पार्क में विभिन्न प्रदर्शनियों तथा उपकरणों द्वारा आगंतुकों को समझाया जाता है कि पृथ्वी का झुकाव ऋतुओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्ष के दौरान सूर्य की गति एवं छाया में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, सन डायल द्वारा समय तथा सूर्य की स्थिति किस तरह मापी जा सकती है, आदि बातें विद्यार्थियों के लिए इस स्थल को एक खुली हवा में स्थित विज्ञान की प्रयोगशाला बना देती हैं।

विज्ञान पर्यटन, ज्ञान का आकर्षण

इस पार्क को एक अनूठे तथा सेल्फ-एक्सप्लेनेटरी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है; जिसमें बाह्य प्रदर्शनियाँ, खगोलीय ढाँचे (एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स) तथा आगंतुकों के लिए सुविधा है। यह पार्क विज्ञानप्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थल बन गया है। आगंतुकों के लिए यहाँ विभिन्न दिलचस्प गतिविधियाँ हैं, जैसे कि वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पर खड़े रहने का अनुभव, रुचिप्रद विज्ञान प्रदर्शनी, प्राकृतिक द्रव्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। इसके साथ; यह पार्क स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार एवं विकास के नए अवसर भी पैदा करता है। यह पार्क विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए एक जीवंत केन्द्र समान है। इस प्रकार; ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क गुजकोस्ट द्वारा एक अनूठी वैज्ञानिक व शैक्षणिक पहल है; जो आगंतुकों के लिए एक अमूर्त भौगोलिक विचार को मूर्त, आकर्षक व सूचनाप्रद अनुभव में परिवर्तित करती है। गुजरात में यह पार्क एक माइल स्टोन समान है, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा को जागृत करेगा। यह पार्क वैज्ञानिक जाति, अनुभवजन्य शिक्षा तथा नवीनता-संचालित सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहन देने की गुजरात की प्रतिबद्ध को मजबूत बनाता है।

अहमदाबाद–धोलेरा के बीच बनेगा 134 किमी लंबा ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड कॉरिडोर

▶▶ साबरमती, गांधीग्राम एवं वस्त्रापुर स्टेशनों पर मेट्रो नेटवर्क से होगा कनेक्ट

▶▶ विधायक श्री अमित ठाकर और डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने किया वस्त्रापुर स्टेशन का दौरा

गुजरात को देश का पहला ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मिलने जा रहा है। अहमदाबाद (सरखेज) से धोलेरा के बीच लगभग 134 किलोमीटर लंबी दोहरी ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR), आगामी धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की डिज़ाइन गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा तथा परिचालन गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

इस परियोजना के अंतर्गत साबरमती, गांधीग्राम एवं वस्त्रापुर स्टेशनों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। साथ ही साबरमती स्टेशन पर बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी तथा मोरैया स्टेशन पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे गुजरात एक विश्वस्तरीय मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा।

इसी क्रम में वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अमित ठाकर ने वस्त्रापुर स्टेशन का दौरा किया। इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में माननीय विधायक श्री अमित ठाकर ने कहा कि जब किसी राज्य में बड़े विकास कार्य होते हैं, तब उससे जुड़े क्षेत्रों में भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। उन्होंने कहा कि धोलेरा में विकसित हो रहे विशाल औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्र को अहमदाबाद के सरखेज क्षेत्र से जोड़ने वाली यह सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना गुजरात के विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा क्षेत्र के सांसद श्री अमित शाह तथा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 20,667 करोड़ की इस परियोजना से वेजलपुर क्षेत्र एवं अहमदाबाद शहर में व्यापक

विकास और निवेश की संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से लोग मात्र 45 मिनट में धोलेरा पहुँच सकेंगे, जिससे रोजगार, आवासीय एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। साथ ही भावनगर क्षेत्र में विकसित हो रहे बंदरगाह एवं औद्योगिक गतिविधियों से भी अहमदाबाद और सरखेज क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाना तथा भारत की लॉजिस्टिक दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

अमेरिका-ईरान तनाव का प्रभाव: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 और सीएनजी की कीमतों में 2 की बढ़ोतरी हुई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर आखिरकार भारत पर भी दिखने लगा है। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह बढ़ोतरी मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण हुई है। विपक्षी दलों ने पहले ही आशंका जताई थी कि पांच राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देगी। हालांकि, सरकार ने उस समय इन दावों को खारिज कर दिया था। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए गए थे। आज, 15 मई को, सरकार ने आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस कदम से महंगाई बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में नई दरों के अनुसार, पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गई है।

सीएनजी की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई

दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी की कीमत अब 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। एक दिन पहले मुंबई में भी सीएनजी की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सीएनजी की कीमत अब 84 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति के बावजूद भारत ने अब तक खुदरा ईंधन की कीमतों में बड़ी वृद्धि करने से परहेज किया है। हालांकि, बढ़ते दबाव के जवाब में अब यह कदम उठाया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु 'EASE' टीम का शुभारंभ

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने महिला सशक्तिकरण, कल्याण एवं सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रगतिशील पहल करते हुए EASE (Empowerment Advocates and Support Enhancement) टीम का शुभारंभ किया है। यह पहल मुंबई सेंट्रल मंडल की अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) डॉ. आरती सिंह परिहार के मार्गदर्शन में की गई है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंडल के विभिन्न विभागों से महिला प्रतिनिधियों को इस टीम के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ताकि मंडल के सभी विभागों

एवं कार्यक्षेत्रों की व्यापक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। EASE टीम नियमित रूप से मुंबई मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों, कार्यालयों तथा विभिन्न कार्यस्थलों का दौरा कर महिला कर्मचारियों एवं स्टाफ सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करेगी। इन संवादों के माध्यम से महिला कर्मचारियों के विचारों, चिंताओं, चुनौतियों तथा सुझावों को अधिक सहज एवं सकारात्मक वातावरण में समझने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, ऐसे संवादों के माध्यम से टीम महिला कर्मचारियों को व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक उन्नति, आत्मविश्वास निर्माण तथा नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

इस पहल का उद्देश्य एक सुरक्षित, समावेशी, सहयोगात्मक एवं सशक्त कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करना भी है, जहाँ महिला कर्मचारी स्वयं को सम्मानित, समर्थित तथा प्रोत्साहित महसूस करें और अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

EASE टीम का गठन लैंगिक समावेशिता को और अधिक सुदृढ़ करने, कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने तथा सकारात्मक एवं प्रगतिशील कार्य संस्कृति के निर्माण के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पोरबंदर से चलने वाली दो जोड़ी ट्रेनें रद्द

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु किए जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से होकर चलने वाली दो जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, रद्द की जाने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

रद्द की गई ट्रेनें:

1. 10.06.2026 एवं 11.06.2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
2. 12.06.2026 एवं 13.06.2026 को शालीमार से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
3. 12.06.2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12949 पोरबंदर-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
4. 14.06.2026 को सांतरागाछी से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12950 सांतरागाछी-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

15 जून को अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे में पेंशन अदालत का आयोजन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबन्धित प्रश्नों के त्वरित निपटारे के लिए 15 जून, 2026 (सोमवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा।

वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ के अनुसार अहमदाबाद मण्डल से जो भी कर्मचारी सेवानिवृत हुए है उन पेंशनर/फेमिली पेंशनर के पेंशन संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अहमदाबाद में दिनांक 15.06.2026 (सोमवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है।

अहमदाबाद मंडल से जो भी कर्मचारी रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं वह पेंशनर/फैमिली पेंशनर अपनी पेंशन संबंधित शिकायतें है वह अपना आवेदन (तीन प्रतियों में) दिनांक 01.06.2026 तक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (स्थापना), अहमदाबाद मण्डल पश्चिम रेलवे, GCS हॉस्पिटल के सामने अमदुपुरा अहमदाबाद को भेज सकते हैं।

आवेदन में अपना नाम, पदनाम, अंतिम वेतन, भर्ती तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि PPO प्रति एवं शिकायत का प्रकार अवश्य दर्ज करें।

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने भावनगर मंडल का संरक्षा निरीक्षण किया

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने दिनांक 14 एवं 15 मई, 2026 को भावनगर मंडल के बोटाद–भावनगर खंड का विस्तृत संरक्षा निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेल संरक्षा, परिचालन दक्षता तथा यात्री सुविधाओं की समीक्षा करना था।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 14 मई, 2026 को अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने बोटाद से भावनगर परा तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया तथा मार्ग में रेल पथ, सिग्नल एवं अन्य संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

इसी दिन उनके करकमलों द्वारा भावनगर परा में नवनिर्मित टाइप-V रेलवे आवासों (5 इकाइयों) का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति

रेलवे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए वृक्षारोपण भी किया गया।

निरीक्षण के दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक ऋत्विक शर्मा तथा मंडल के सभी शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके पश्चात अपर महाप्रबंधक ने भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में शाखा अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों, संरक्षा उपायों एवं परिचालन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही नवनिर्मित मंडल कार्यालय भवन का भी अवलोकन किया।

दिनांक 15 मई, 2026 को श्री प्रदीप कुमार ने बोटाद रेलवे स्टेशन का संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर उपलब्ध संरक्षा एवं यात्री सुविधाओं की समीक्षा की गई। इसी दिन उनके करकमलों द्वारा बोटाद में नवनिर्मित रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। निरीक्षण के समय मंडल के संबंधित शाखा अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस दो दिवसीय निरीक्षण के दौरान अपर महाप्रबंधक ने संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए तथा भावनगर मंडल में अधोसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

29 मई से 26 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच विशेष किराये पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, इस विशेष ट्रेन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा—

ट्रेन संख्या 09257 भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 29 मई, 2026 से 26 जून, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को भावनगर टर्मिनस से दोपहर 14:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन शनिवार को प्रातः 10:55 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09258 शकूर बस्ती–भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई, 2026 से 27 जून, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को शकूर बस्ती से दोपहर 13:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रविवार को प्रातः 08:50 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

दोनों दिशाओं में यह ट्रेन निम्नलिखित स्टेशनों पर ठहरेगी— भावनगर परा, सिहोर (गुजरात), धोला, बोटाद, धंधुका, धोलका, सरखेज, गांधीग्राम, चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी जंक्शन, गुड़गांव एवं दिल्ली कैंट।

इस विशेष ट्रेन में द्वितीय श्रेणी, शयनयान, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी तथा सेकंड एसी श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09257 के लिए टिकटों की बुकिंग 17 मई, 2026 (रविवार) से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

वडोदरा रेलवे स्टेशन बना और स्मार्ट, डिजिटल एक्सेस बोर्ड और 'सारथी' इलेक्ट्रिक कार्ट सेवा शुरू

Vadodara। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने यात्रियों की सुविधाओं को अधिक आधुनिक, सुगम और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर डिजिटल एक्सेस बोर्ड और बैटरी ऑपरेटेड कार्ट सेवा की शुरुआत की है। इन नई सुविधाओं का उद्घाटन सांसद Hemang Joshi ने किया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके, वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

इस पहल को रेलवे के स्मार्ट स्टेशन और यात्री-केंद्रित विकास अभियान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन परिसर में आसान मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने कहा कि वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई दोनों सुविधाएं यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल देंगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल एक्सेस बोर्ड एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिस्टम के रूप में कार्य करेगा, जहां यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करते ही विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इससे यात्रियों को टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म, सुरक्षा सेवाओं, लिफ्ट और अन्य जरूरी स्थानों को खोजने में आसानी होगी।

सांसद ने विशेष रूप से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई "सारथी" इलेक्ट्रिक कार्ट सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सेवा देश में पहली बार शुरू की गई है और यह रेलवे के समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगी। उन्होंने वडोदरा मंडल की पूरी टीम और मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके को इस अभिनव पहल के लिए बधाई दी।

इस दौरान सांसद ने स्टेशन परिसर में कार्यरत लाइसेंस सहायकों से भी मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके हितों की रक्षा सरकार और रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और सहायकों को हर संभव सहयोग और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे लगातार आधुनिक तकनीक और स्मार्ट सुविधाओं को स्टेशन स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल एक्सेस बोर्ड यात्रियों के लिए एक स्मार्ट सूचना केंद्र की तरह काम करेगा। स्टेशन पर आने वाले यात्री को अब आसानी से पता चल सकेगा कि रेलवे सुरक्षा बल का कार्यालय कहां है, टिकट खिड़की कहां स्थित है, लिफ्ट और एस्केलेटर किस दिशा में हैं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं किस स्थान पर उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक कार्ट इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटे आकार की यह कार्ट स्टेशन परिसर के भीतर आसानी से संचालित हो सकती है और इसकी विशेषता यह है कि यह लिफ्ट के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच सकती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। यह कार्ट यात्रियों को स्टेशन प्रवेश द्वार से सीधे उनकी ट्रेन तक पहुंचाने में मदद करेगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार ने बताया कि डिजिटल एक्सेस बोर्ड को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR पहल के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों के स्टेशन अनुभव को अधिक सहज, तनावमुक्त और सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि वडोदरा स्टेशन पर लगाया गया यह डिजिटल बोर्ड स्टेशन के विभिन्न हिस्सों की जानकारी आसान भाषा और स्पष्ट दिशा संकेतों के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इस डिजिटल सिस्टम में प्लेटफॉर्म की जानकारी, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजन सुविधाएं, फूड स्टॉल, सुरक्षा सेवाएं और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का विवरण उपलब्ध रहेगा। विशेष रूप से पहली बार यात्रा करने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी।

नरेन्द्र कुमार ने कहा कि नई बैटरी चालित कार्ट सेवा केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि यह सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी ताकि किसी भी समय आने-जाने वाले यात्रियों को सहायता मिल सके।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार वडोदरा मंडल द्वारा शुरू की गई ये पहलें केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रेलवे के डिजिटल परिवर्तन और स्मार्ट स्टेशन विकास अभियान का हिस्सा हैं। रेलवे अब पारंपरिक सेवाओं को तकनीक आधारित आधुनिक सुविधाओं में बदलने पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सुविधाएं रेलवे स्टेशनों को अधिक संगठित और यात्री अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। साथ ही, डिजिटल सूचना प्रणाली और आधुनिक सेवाओं के माध्यम से रेलवे को गैर-किराया राजस्व यानी नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

वडोदरा मंडल ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इस तरह की और भी आधुनिक सुविधाएं शुरू की जाएंगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि उनका लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक, सुलभ और सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है। पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल आने वाले समय में स्टेशन विकास और डिजिटल सुविधाओं के क्षेत्र में और नए प्रयोग करने की तैयारी कर रहा है।

सूरत कपड़ा बाजार में बढ़ेगा पार्सल ढुलाई शुल्क, 1 जून से प्रति पार्सल 15 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे

Surat। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब माने जाने वाले सूरत कपड़ा बाजार में अब व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने जा रहा है। सूरत जिला टेक्सटाइल मार्केटिंग ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन ने पार्सल ढुलाई शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यूनियन की घोषणा के अनुसार 1 जून 2026 से प्रत्येक पार्सल पर 15 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इस निर्णय का सीधा असर कपड़ा व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों और देशभर में कपड़ा मंगाने वाले व्यापारियों पर पड़ने की संभावना है।

यूनियन का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और परिचालन खर्चों में हुई वृद्धि के कारण यह फैसला लेना जरूरी हो गया था। यूनियन के अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा और प्रवक्ता शान खान ने बताया कि पिछले कुछ समय में ईंधन की कीमतों, परिवहन खर्च, मजदूरी और अन्य आवश्यक सेवाओं की लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसी स्थिति में पुराने शुल्क पर काम करना मजदूरों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता जा रहा था।

सूरत का कपड़ा बाजार देशभर में अपने विशाल व्यापारिक नेटवर्क के लिए जाना जाता है। यहां से रोजाना लाखों मीटर कपड़ा और हजारों पार्सल देश के अलग-अलग राज्यों में भेजे जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में पार्सल मजदूरों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाजार में माल की ढुलाई, लोडिंग-अनलोडिंग और समय पर पार्सल पहुंचाने का काम बड़ी संख्या में श्रमिकों के माध्यम से संचालित होता है। ऐसे में ढुलाई शुल्क में बदलाव का असर पूरे व्यापारिक ढांचे पर दिखाई देता है।

यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि महंगाई के कारण मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि मजदूरी और पारिश्रमिक उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाए हैं। इसके अलावा डीजल और परिवहन से जुड़े अन्य खर्चों में हुई वृद्धि का सीधा असर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर पड़ा है। इसी को देखते हुए यूनियन ने सभी पक्षों से चर्चा के बाद पार्सल शुल्क में संशोधन का निर्णय लिया। यूनियन ने बताया कि इस संबंध में कपड़ा बाजार के विभिन्न मार्केट प्रबंधन को औपचारिक पत्र भेजा जाएगा ताकि नई दरों की जानकारी समय रहते सभी व्यापारियों तक पहुंच सके। साथ ही पार्सल मजदूरों और ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने व्यापारिक संपर्कों को नई दरों के बारे में अवगत कराएं। नई दरें लागू होने के बाद प्रत्येक पार्सल पर 15 रुपये अतिरिक्त शुल्क जुड़ जाएगा।

व्यापारियों का मानना है कि इससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, जिसका असर अंततः कपड़ा कारोबार की कुल लागत पर भी पड़ सकता है। हालांकि कई व्यापारियों ने यह भी माना कि बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों और परिवहन से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सूरत कपड़ा बाजार देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहां का टेक्सटाइल उद्योग लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और देश-विदेश के बाजारों तक कपड़े की सप्लाई करता है। ऐसे में बाजार में होने वाला कोई भी आर्थिक बदलाव व्यापक प्रभाव डालता है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवहन और लॉजिस्टिक लागत में बढ़ोतरी का असर धीरे-धीरे खुदरा बाजार तक भी पहुंच सकता है। ट्रांसपोर्ट और पार्सल सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में परिचालन लागत तेजी से बढ़ी है। डीजल कीमतों के अलावा वाहन रखरखाव, श्रमिक वेतन और अन्य खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यदि शुल्क में समय-समय पर संशोधन नहीं किया जाए तो कामकाज प्रभावित होने लगता है।

व्यापारिक संगठनों की ओर से फिलहाल इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ व्यापारियों ने इसे आवश्यक कदम बताया है, जबकि कुछ का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। हालांकि अधिकांश व्यापारियों का मानना है कि यदि यह वृद्धि मजदूरों और परिवहन व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए की जा रही है तो इसे संतुलित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि नई दरें 1 जून 2026 से प्रभावी होंगी और इसके बाद सभी पार्सल पर संशोधित शुल्क लागू माना जाएगा। आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर बाजार में और चर्चाएं तेज होने की संभावना है, क्योंकि सूरत का कपड़ा उद्योग देश के सबसे बड़े व्यापारिक नेटवर्क में से एक माना जाता है।

सूरत में अधिक मास महोत्सव की भव्य शुरुआत आज से, श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में पूरे महीने होंगे विशेष मनोरथ और दर्शन

Surat। डुमस रोड स्थित Shri Govardhannathji Haveli में रविवार 17 मई से ज्येष्ठ अधिक मास महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। पुष्टिमार्गीय परंपरा के अनुसार आयोजित होने वाला यह महोत्सव वैष्णव समाज के लिए अत्यंत विशेष और आध्यात्मिक महत्व रखता है। प्रत्येक तीन वर्ष में आने वाले अधिक मास को भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक साधना का दुर्लभ अवसर माना जाता है, जिसके चलते सूरत सहित आसपास के क्षेत्रों के वैष्णवों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

पुष्टिमार्ग की मान्यताओं के अनुसार अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, सामान्य महीनों से अलग आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस अवधि में यह माना जाता है कि जहां वर्ष के अन्य महीनों में भक्त भगवान की सेवा करते हैं, वहीं पुरुषोत्तम मास में स्वयं श्री ठाकोरजी भक्तों के बीच स्नेह और सेवा ग्रहण करने पधारते हैं। इसी दिव्य भावना के कारण वैष्णव समाज में अधिक मास को विशेष श्रद्धा और उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में पूरे अधिक मास के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम विशेष मनोरथ, झांकियां और दर्शनों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ रविवार सुबह 8 बजे श्रीनाथजी प्रागट्य झांकी के साथ होगा। इसके बाद शाम के समय सप्त निधि स्वरूप दर्शन आयोजित किए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

महोत्सव के दौरान हवेली परिसर को पारंपरिक और आध्यात्मिक सजावट से सजाया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस पूरे माह में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मनोरथों के माध्यम से व्रज संस्कृति और पुष्टिमार्गीय परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भाव, भक्ति और सांस्कृतिक अनुभव का भी विशेष अवसर होगा।

अधिक मास महोत्सव के अंतर्गत कई विशेष मनोरथों और झांकियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें द्वीपलना मनोरथ, त्रिवेणी हिंडोला, श्रीजी निकुंज दर्शन, षटऋतु मनोरथ, व्रजकमल मनोरथ, 84 बैठकजी दर्शन, चूंदड़ी मनोरथ, मानसी परिक्रमा, रमण रेती मनोरथ, 84 मालाजी मनोरथ, वन भोजन लीला, नव निकुंज मनोरथ, विवाह खेल, चंदन चोली तथा जल में दीप मनोरथ जैसे कार्यक्रम प्रमुख रहेंगे। इन आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को व्रज की लीलाओं और श्रीनाथजी की विभिन्न भावनात्मक सेवाओं के दर्शन कराए जाएंगे। धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ प्रतिदिन शाम 5 बजे कथाकार भरतभाई दवे द्वारा अधिक मास कथा का आयोजन भी किया जाएगा। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को पुरुषोत्तम मास का महत्व, व्रज भक्ति, श्रीकृष्ण की लीलाओं और पुष्टिमार्गीय सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आयोजकों का मानना है कि कथा श्रवण से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और धार्मिक लाभ प्राप्त होगा।

महोत्सव के दौरान आने वाली दोनों प्रमुख एकादशियों — 27 मई और 11 जून — को विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों श्री राधा पुरुषोत्तम को तुलसी अर्पण का विशेष आयोजन रखा गया है। वैष्णव परंपरा में तुलसी अर्पण को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इसमें भाग लेने की संभावना है।

श्री गोवर्धन ट्रस्ट ने अधिक मास महोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था, भक्ति कार्यक्रमों और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रस्ट ने वैष्णव समाज से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सभी मनोरथों और विशेष दर्शनों का लाभ लेने की अपील की है।

सूरत में पुष्टिमार्गीय परंपरा का विशेष प्रभाव रहा है और यहां बड़ी संख्या में वैष्णव परिवार निवास करते हैं। ऐसे में अधिक मास महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का भी रूप ले लेता है। हर तीन वर्ष में आने वाले इस विशेष मास का श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार करते हैं और पूरे महीने भक्ति, सेवा, संकीर्तन और धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं।

धार्मिक जानकारों के अनुसार अधिक मास को आत्मशुद्धि, सेवा और भक्ति का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस दौरान किए गए जप, तप, दान और सेवा को विशेष फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि इस अवधि में मंदिरों और हवेलियों में विशेष आयोजन किए जाते हैं और श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

डुमस रोड स्थित श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में शुरू हो रहा यह महोत्सव पूरे अधिक मास तक सूरत के धार्मिक वातावरण को भक्तिमय बनाए रखेगा। आयोजकों को उम्मीद है कि इस दौरान हजारों श्रद्धालु दर्शन और कथा का लाभ लेने पहुंचेंगे और अधिक मास की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे।

विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से भारतीय बाजार में बढ़ा दबाव, बड़े दिग्गज शेयरों में तेज गिरावट

India। भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली का दबाव और गहरा होता जा रहा है। वर्ष 2024 के अंत से लेकर अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय बाजार से लगभग 53 अरब डॉलर की निकासी कर दी है। इसका असर न केवल शेयर बाजार बल्कि रुपये की स्थिति और निवेशकों के भरोसे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। विदेशी पूंजी के लगातार बाहर जाने से बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और कई बड़े ब्लूचिप शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सितंबर 2024 से लेकर 2026 के बीच MSCI India Index में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बैंकिंग, आईटी, टेलीकॉम, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख सेक्टरों पर व्यापक असर डाला है। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये पर भी दबाव बढ़ा है।

मार्च 2026 तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों ने सबसे अधिक बिकवाली HDFC Bank में की। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच बैंक के करीब 47.95 करोड़ शेयर बेचे गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 41,449 करोड़ रुपये रही। इस भारी बिकवाली के चलते बैंक के शेयर में 26.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अधिक होने के कारण बिकवाली का असर ज्यादा दिखाई दिया।

इसी तरह Kotak Mahindra Bank के 29.41 करोड़ शेयर लगभग 11,729 करोड़ रुपये में बेचे गए। इस दौरान कंपनी के शेयर में करीब 19.72 प्रतिशत की गिरावट आई। निजी बैंकिंग क्षेत्र में लगातार बिकवाली से निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है।

टेलीकॉम सेक्टर की प्रमुख कंपनी Bharti Airtel भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली से अछूती नहीं रही। कंपनी में करीब 11,287 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेची गई। वहीं ICICI Bank के 8.18 करोड़ शेयर 10,973 करोड़ रुपये में ऑफलोड किए गए, जिसके चलते बैंक के शेयर में 10.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बिकवाली का दबाव साफ दिखाई दिया। Infosys के 5.76 करोड़ शेयर लगभग 8,112 करोड़ रुपये में बेचे गए। इसके बाद कंपनी के शेयर में 22.58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी बाजार में मांग को लेकर चिंताओं का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी पड़ा है।

देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल Reliance Industries के 5.54 करोड़ शेयर 7,815 करोड़ रुपये में बेचे गए। इससे कंपनी के शेयर में 14.42 प्रतिशत की गिरावट आई। रिलायंस जैसे बड़े समूह में विदेशी निवेशकों की बिकवाली को बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Eternal के 35.09 करोड़ शेयर 9,147 करोड़ रुपये में बेचे गए। इसके बाद कंपनी का शेयर 17.65 प्रतिशत टूट गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार टेक और इंटरनेट आधारित कंपनियों में जोखिम बढ़ने की आशंका के कारण विदेशी निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।

ऑटो सेक्टर में भी भारी दबाव देखा गया। Maruti Suzuki के 0.52 करोड़ शेयर 7,409 करोड़ रुपये में बेचे गए, जिससे कंपनी का शेयर 26.30 प्रतिशत तक गिर गया। इसी प्रकार आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Tata Consultancy Services के 2.58 करोड़ शेयर 7,162 करोड़ रुपये में बिके और शेयर में 26.43 प्रतिशत की गिरावट आई।

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी Larsen & Toubro के 1.74 करोड़ शेयर 6,631 करोड़ रुपये में बेचे गए। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का शेयर 14.19 प्रतिशत नीचे आया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक निवेशकों की जोखिम से बचने की रणनीति का असर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी पड़ा है।

विश्लेषकों के अनुसार विदेशी निवेशकों की यह बिकवाली कई वैश्विक और घरेलू कारणों से जुड़ी हुई है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका, डॉलर की मजबूती और उभरते बाजारों में जोखिम बढ़ने जैसी वजहों से विदेशी निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय बाजार में लंबे समय तक तेज तेजी के बाद मुनाफावसूली भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है।

हालांकि बाजार विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति अब भी मजबूत बनी हुई है। घरेलू निवेशकों की सक्रिय भागीदारी और मजबूत आर्थिक वृद्धि दर बाजार को सहारा देने का काम कर रही है। फिर भी विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार में दबाव और उतार-चढ़ाव बना रहने की संभावना जताई जा रही है।

एआई की वैश्विक दौड़ में बड़ा दांव, दुनिया की सबसे बड़ी AI टेक कंपनी बनने की तैयारी में TCS

Tata Consultancy Services ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। कंपनी का कहना है कि वह अब पारंपरिक आईटी सेवाओं से आगे बढ़कर पूर्ण एआई इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक K Krithivasan ने बताया कि टीसीएस के शीर्ष 139 ग्राहकों में से 130 पहले ही कंपनी को अपना एआई सेवा भागीदार चुन चुके हैं। इसे वैश्विक स्तर पर टीसीएस की बढ़ती एआई क्षमता और भरोसे का संकेत माना जा रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कृतिवासन ने कहा कि बीता वर्ष एंटरप्राइज एआई के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। उनके अनुसार अब कंपनियां केवल परीक्षण या सीमित प्रयोगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर एआई तकनीक को अपने कारोबारी ढांचे में शामिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीसीएस की रणनीति केवल सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी "इंटेलिजेंस-ड्रिवन टेक्नोलॉजी पार्टनर" बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। टीसीएस का कहना है कि वह ग्राहकों को एआई आधारित संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना चाहती है, जिसमें डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई और बिजनेस इंटेलिजेंस जैसी सेवाएं शामिल होंगी। कंपनी मानती है कि आने वाले वर्षों में एआई हर उद्योग का मूल आधार बनने जा रहा है और जो कंपनियां समय रहते इस बदलाव को अपनाएंगी, वही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगी। कंपनी के मुताबिक पांच करोड़ डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व वाले उसके 139 बड़े वैश्विक ग्राहकों में से 130 पहले ही टीसीएस की एआई सेवाओं को अपना चुके हैं। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि बड़े उद्यम अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में एआई को प्राथमिकता दे रहे हैं और टीसीएस इस बदलाव का बड़ा भागीदार बनती जा रही है। टीसीएस ने एआई विस्तार को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों के कौशल विकास पर भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। कंपनी के अनुसार वर्तमान में उसके 2.70 लाख से अधिक कर्मचारियों के पास उन्नत एआई कौशल हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक बताई गई है। कंपनी का कहना है कि भविष्य की तकनीकी जरूरतों को देखते हुए कर्मचारियों को लगातार री-स्किल और अप-स्किल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आईटी उद्योग में अब प्रतिस्पर्धा केवल कोडिंग या पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि एआई क्षमता, डेटा इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन पर केंद्रित हो गई है। ऐसे में टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित कर भविष्य की मांग के अनुरूप तैयार कर रही हैं। टीसीएस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देश की कई बड़ी डिजिटल परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। कंपनी के अनुसार सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी Government e-Marketplace (GeM) को दुनिया के सबसे बड़े सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदलने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नेपाल सीमा के करीब रणनीतिक रूप से अहम दरभंगा एयरपोर्ट अब CISF सुरक्षा घेरे में, बढ़ेगी विमानन सुरक्षा की ताकत

Darbhanga। उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में शामिल Darbhanga Airport की सुरक्षा अब औपचारिक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी Central Industrial Security Force (सीआईएसएफ) को सौंप दी गई है। इस अवसर पर हवाई अड्डा परिसर में विशेष इंडक्शन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस कदम को उत्तर बिहार में विमानन सुरक्षा और सामरिक अवसंरचना की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है।

सीआईएसएफ की तैनाती के साथ दरभंगा देश का 72वां ऐसा हवाई अड्डा बन गया है, जिसे इस केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा प्राप्त हुई है। वहीं बिहार में पटना और गया के बाद यह तीसरा एयरपोर्ट है, जहां अब सीआईएसएफ सुरक्षा व्यवस्था संभालेगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दरभंगा एयरपोर्ट की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र नेपाल सीमा के करीब होने के कारण संवेदनशील माना जाता है।

इंडक्शन समारोह में बिहार के उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary, दरभंगा सांसद Gopal Ji Thakur, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन, बिहार पुलिस महानिदेशक विनय कुमार तथा सीआईएसएफ एयरपोर्ट सेक्टर की अपर महानिदेशक बिनिता ठाकुर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान अधिकारियों ने एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था, सामरिक महत्व और यात्री सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की।

प्रारंभिक चरण में एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए कुल 145 सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। इनमें विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को शामिल किया गया है, जो आधुनिक विमानन सुरक्षा मानकों के अनुसार एयरपोर्ट की निगरानी करेंगे। अधिकारियों के अनुसार यह तैनाती केवल सामान्य सुरक्षा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बहु-स्तरीय और तकनीक आधारित सुरक्षा ढांचे के तहत की जाएगी।

दरभंगा एयरपोर्ट की सामरिक अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह लगभग 729 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा के नजदीक स्थित है। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस क्षेत्र में सीमा पार तस्करी, अवैध गतिविधियों और ड्रोन जैसे आधुनिक खतरों को लेकर सतर्क रही हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती को राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एयरपोर्ट केवल यात्री आवागमन के केंद्र नहीं होते, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक निगरानी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है और यहां यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इस कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

दरभंगा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना स्टेशन परिसर के भीतर सिविल एन्क्लेव के रूप में संचालित होता है। यही वजह है कि यहां सुरक्षा मानकों को और अधिक संवेदनशील माना जाता है। एयरफोर्स स्टेशन के भीतर स्थित होने के कारण नागरिक और सैन्य गतिविधियों के बीच संतुलित और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत रहती है। सीआईएसएफ अब इस पूरे ढांचे को पेशेवर तरीके से संचालित करेगा। नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत यात्रियों और उनके सामान की उन्नत जांच, एंटी-सबोटाज चेकिंग, सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण तंत्र और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। एयरपोर्ट परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी तंत्र भी विकसित किया गया है।

आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एयरपोर्ट पर कई विशेष इकाइयों की भी तैनाती की गई है। इनमें क्विक रिएक्शन टीम (QRT), बम निरोधक दस्ता (BDS) और विस्फोटक पहचान में प्रशिक्षित के-9 डॉग स्क्वॉड शामिल हैं। ये टीमें किसी भी आपात स्थिति या सुरक्षा खतरे से तुरंत निपटने में सक्षम होंगी।

दरभंगा एयरपोर्ट का विकास केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (UDAN) के तहत तेजी से हुआ है। कुछ वर्षों पहले तक सीमित सुविधाओं वाला यह एयरपोर्ट अब उत्तर बिहार के प्रमुख हवाई संपर्क केंद्रों में गिना जाता है। इससे मिथिला और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को देश के बड़े शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिली है, जिससे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।

समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को देखते हुए यहां मजबूत सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार सीआईएसएफ की तैनाती से न केवल यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि क्षेत्र को एक मजबूत सुरक्षा कवच भी मिलेगा। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन ने कहा कि बल आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित मानव संसाधन और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानकों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट सुरक्षा केवल जांच तक सीमित नहीं होती, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और सहज अनुभव देना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती आने वाले समय में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को और मजबूत करेगी। इससे यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ेगा और एयरपोर्ट के विस्तार तथा नई उड़ानों के लिए भी सकारात्मक माहौल तैयार होगा। साथ ही यह कदम उत्तर बिहार में बढ़ती हवाई गतिविधियों और सामरिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है।